

अन्ततोगत्वा देवेन्द्र फड़नवीस का नाम फाइनल हो गया महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के लिए

आज आज़ाद मैदान में फड़नवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस का कल मुम्बई के "आज़ाद मैदान" में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना पूरी तरह से तय है। वे तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा नेतृत्व ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद के लिये अपनी पसन्द के रूप में उनके नाम को अन्तिम रूप दे दिया। इस प्रकार लम्बे समय तक चले इस असमंजस का अन्त हो गया है कि राज्य के इस सर्वोच्च पद पर कौन होगा। इस निर्णय के शीघ्र बाद ही, उनका नाम बुधवार को एक मीटिंग में नव-निर्वाचित विधायकों के समक्ष रख दिया गया तथा उनके अनुमोदन के बाद, उनके चयन को अन्तिम रूप मिल गया।

- विधायक दल की बैठक में देवेन्द्र फड़नवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और विधायकों ने तुरंत उसका अनुमोदन कर दिया।
- उसके बाद फड़नवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार के साथ राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मिलने गए तथा सरकार बनाने का दावा पेश किया।
- इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा "सस्पेंस" भी खत्म हो गया। पहले दिन से ही यह स्पष्ट था कि भाजपा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि, महायुति के 230 विधायकों में से 132 विधायक भाजपा के हैं।

ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे तथा एन.सी.पी. नेता अजित पवार के साथ राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से भेंट की तथा सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया।

भाजपा विधायकों की मीटिंग में, फड़नवीस ने कहा कि विधायक दल का नेता मनोनीत होना उनके लिये सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 132 विधायकों के समर्थन के बिना, वे इस स्थिति में नहीं होंगे।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को, उनके समर्थन के लिये, धन्यवाद दिया और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार से महाराष्ट्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि महायुति की विजय प्रधानमंत्री के नारे "एक हैं तो सेफ हैं" के कारण हुई है।

भाजपा की कोर कमेटी द्वारा किये गये फड़नवीस के चयन से महाराष्ट्र में इस बात को लेकर 11 दिन से चल रहे असमंजस पर विराम लग गया है कि

मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव-परिणाम, जिसमें महायुति ने विधानसभा की 288 में से 230 सीटें जीती थीं, के बाद, शिवसेना के नेता यह दबाव डाल रहे थे कि गठबंधन ने शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था तथा इसलिये वे ही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिये। लेकिन भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिन 148 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, उनमें से उसने 132 सीटें जीती हैं, इसलिये इस बार शीर्ष पद पर उसका दावा रहेगा। अन्ततोगत्वा, शिंदे ने यह बात सार्वजनिक रूप से कह दी कि वे सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे तथा मुख्यमंत्री पद के सिलसिले में वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय को स्वीकार कर लेंगे।

शिंदे के पास इतनी विधायक संख्या थी भी नहीं, कि वे ज्यादा मोल-भाव कर सकते, क्योंकि विधानसभा में बहुमत के आँकड़े तक पहुँचने के लिये भाजपा को किसी एक मित्र दल की ही जरूरत थी, तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार, एन.सी.पी. अपना समर्थन देने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक भाषा विवाद में उलझा है...

- लक्ष्मण वैकट कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। कर्नाटक जहां कथित रूप से उन उत्तर भारतीय प्रवासियों से जुड़ा रहा है, जो स्थानीय भाषा का सम्मान नहीं करते हैं और उसे सीखना भी नहीं चाहते हैं, पर लगता है कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और केरल ने इसका हल निकाल लिया है और अप्रवासियों को बोल-चाल के लायक तमिल व मलयालम सिखाना शुरू कर दिया है।

केरल तो पहले से ही माइग्रेन्ट्स

- और तमिलनाडु व केरल में प्रवासियों को काम चलाऊ तमिल व मलयालम सिखाई जा रही है, ताकि, राज्य में शांति व्यवस्था में खलल न पड़े।

लेबर के सम्बंध में सकारात्मक नीति पर अमल करता रहा है, वहां माइग्रेन्ट्स लेबर को मलयालम सिखाई जाती है। यहां मजदूरों के लिए कई अच्छी योजनाएं चलाई जाती हैं। यहां आने वाले मजदूर भी काम चलाऊ मलयालम सीख लेते हैं।

तमिलनाडु में भी बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर आते हैं और इन मजदूरों का जीवन आसान बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इन्हें तमिल भाषा सिखाना शुरू कर दी है, ताकि वे बस का रुट और साइन बोर्ड पढ़ सकें। तमिलनाडु में मोबाइल ऐप से भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हुए

पर अपनी रज़ामंदी देने से पहले उन्होंने पूरी मशक्कत की मुख्यमंत्री पद पाने के लिए

-श्री नन्द झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। एकनाथ शिंदे ने अपनी हठ छोड़ दी है तथा उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई एक मीटिंग में अपनी बात पूरी जोरदारी के साथ रखते हुये, उनसे कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाये तथा मुख्यमंत्री के रूप में कम से कम पहले छः महीने काम करने दिया जाये। लेकिन शाह ने उनके इस विचार को सिर से खारिज कर दिया था तथा कह दिया कि इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी तथा राज्य-प्रशासन के पास एक उलझन भरा संदेश जायेगा।

यह मीटिंग 28 नवम्बर को हुई थी। इससे एक दिन पहले शिंदे ने यह कह दिया था कि वे सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे तथा भाजपा हाईकमान जो भी निर्णय लेगी, वह उन्हें स्वीकार होगा। समझा जाता है कि शाह के साथ हुई मीटिंग में, जिसमें देवेन्द्र फड़नवीस तथा एन.सी.पी. नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल तथा सुनील तटकरे भी मौजूद थे, शिंदे ने शाह को भाजपा का यह वादा याद दिलाया था कि अगर महायुति सत्ता में लौटता है तो उन्हें ही (शिंदे) मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन

- शिंदे के समर्थकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने अमित शाह को यहां तक कहा कि एकनाथ शिंदे के कुशल नेतृत्व के कारण ही महायुति को बहुमत मिला है इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलना ही चाहिए।
- शिंदे ने अन्ततोगत्वा अमित शाह के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि उन्हें कम से कम शुरू के छः महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए बाद में हटा दिया जाए, पर शाह ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।
- शिंदे द्वारा उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार करने का एक बड़ा कारण यह था कि शिंदे के सौदेबाजी करने के प्रयास के दौरान महायुति गठबंधन के पावर समीकरणों में काफी बदलाव आया था।
- एन.सी.पी. मूलतः भाजपा की मदद करने पर खुलकर उतर आई थी और इससे भाजपा, शिंदे का दबाव आसानी से झेल गई।

भाजपा ने इस दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि भगवा पार्टी को "तकरीबन स्पष्ट बहुमत" मिला है। इन परिस्थितियों में शिंदे को मुख्यमंत्री पद सौंपना गलत होगा। भाजपा नेताओं ने शिंदे से पूछा था कि अगर दोनों के बीच की भूमिकाएं उलट गई होती तो वे क्या करते। अभी-अभी समाप्त हुये चुनावों में, भाजपा ने विधान सभा की 288 में 132 सीटें जीती हैं

तथा सेना ने 57 सीटें जीती हैं। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें जीती थीं तथा फड़नवीस, एन.सी.पी. के बाहरी समर्थन के साथ, मुख्यमंत्री चुन लिये गये थे। अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के एक दिन बाद, शिंदे, अस्वस्थ होने के कारण, सतारा जिले में स्थित अपने गाँव चले गये थे। वे रविवार को मुम्बई वापस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)




1

सबसे पहले आरई के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं

2

पावती/संदर्भ संख्या प्राप्त करें

3

यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका कोई निवारण नहीं किया जाता है या आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर या सीआरपीसी** को डाक द्वारा भेजकर आरबीआई लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई)* के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इन चरणों का पालन करें



आरबीआई कहता है... जानकार बनिए, सतर्क रहिए!



आरबीआई लोकपाल से सीधे शिकायत दर्ज करने पर वह अस्वीकृत हो सकती है.



अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/ios> पर विजिट करें फ़ीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

*बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट, क्रेडिट सूचना कंपनियां.
** सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.